THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Passenger car industry is delicensed and no approval of Government is necessary for setting up a car unit. Government has also not received any foreign collaboration proposal from Toyota Motors Corporation of Japan and Kirloskar Group for setting up a car project in Greater Noida, Uttar Pradesh.

Impact of new Exim Policy on SSIs

3093. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether his Ministry has recently reviewed the impact of New Exim policy on small scale industries;

(b) if so, the outcome thereof;

(c) whether Government are aware that industrial bodies like FICCI have cautioned about likely adverse effect of the Exim policy on small scale sector as the body feels that the policy would encourage antidumping activities by foreign countries on material imported by Indian small scale sector; and

(d) whether Government have received some representations in that regard?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (d) While the Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries is consulted by the Ministry of Commerce in formulation of the Exim policy, it is the primary responsibility of the Commerce Ministry to formulate and implement the Exim Policy which inter-alia includes measures necessary for providing required protection to domestic industry including the small-scale industry. The new Exim Policy has been announced only recently and it is too early to review it for making a definite impact assessment on the small scale sector. The new Exim Policy has been discussed at various forms including the round table discussion organised by FICCI on 09th April, 1997. In the background paper prepared by the FICCI for the round table discussions, likely impact of reducing the list of negative items for import by 542 has been analysed. According to FICCI, this is likely to adversely affect all the SSI category units manufacturing these items. FICCI has also suggested measures for strengthening enforcement of anti-dumping laws so that foreign companies including multinationals do not indulge in dumping of their products allowed to be imported under the liberalised Exim Policies.

राज्य सरकारों द्वारा खनन पट्टा

3094. **डा. बाई. लक्ष्मी प्रसादः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि खनन संबंधी पट्टे देने का अधिकार राज्य सरकार को है। जबकि पर्यावरण संबंधी अनुमति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती है;

(ग) क्या इसका नदान ऐसी समन्त्रय एजेन्ती नहीं है जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी सदस्य हों;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में संगत नियमों में संशोधन अपेक्षित है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री वीरेन्द्र प्रसाद वैश्य):

(a) से (च) खनिज रियायतों की मंजूरी खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित की जाती है। खनिज रियायतों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किये जाते हैं। केन्द्र सरकार का अनुमोदन केवल खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की अनुसूची -1 के अधीन आने वाले खनिजों के लिए अवश्यक है। दूसरे और पर्यावरण के बारे में अनुमति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम 1986 और वन (संरक्षण) अधिनयम 1980 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है कोई भी खनन पट्टा और पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने से पहले राज्य सरकार को वन (संरक्षण) अधिनयम 1980 और अन्य लागू अधिनयम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना पढ़ता है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन उक्त अधिनियमों और नियमों में किया गया है।